

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VII/159
No.E(P&A)II-2017/HW-1

RBE No. 83/2020
New Delhi, dated 29.09.2020

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.

**Sub:-Payment of Night Duty Allowance (NDA) pursuant to the
recommendations of 7th Central Pay Commission-reg.**

++++++

Please refer to Board's letter of even number dated 08.03.2018 (RBE No.36/2018) whereby the rates for revision of Night Duty Allowance (NDA) have been issued.


2. The matter has been reviewed based on the orders received from DoPT, the nodal Deptt. of Govt. on NDA. The President is pleased to decide that the hourly rate of NDA shall be equal to $\{Basic\ Pay + Dearness\ Allowance\}/200$ which would be admissible to eligible categories of non-gazetted Railway Servants classified under chapter XIV of the Railway Act, 1989 read with the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 for work put in during the period from 2200 hrs to 0600 hrs. The ceiling of basic pay for entitlement of Night Duty Allowance shall be ₹43600/- per month. The rate should be worked out separately for each employee. The present formulation of weightage of 10 minutes for every hour of duty performed between the hours of 22:00 and 06:00 would continue.

3. The grant of NDA shall be subject to furnishing of a certificate by the supervisor concerned that Night Duty is essential.

4. These instructions will be applicable w.e.f 01.07.2017.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Hindi version is enclosed.


(N.P. Singh)
Jt. Director, Estt.(P&A)
Railway Board

No.E(P&A)II-2017/HW-1

New Delhi, dated 29.09.2020

Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222,
Rail Bhawan, New Delhi.


For Member Finance, Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

ए.टि.पी.सी.-XIV/159
सं.ई(पी एंड ए)।-2017/एचडब्ल्यू-1

आरबीई सं. 83/2020
नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2020

महाप्रबंधक/सीएओ,
सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयों।

विषय: भारतई केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रावि इयूटी भत्ते का भुगतान।

कृपया बोर्ड के दिनांक 08.03.2018 के समसंख्यक पर (आरबीई सं.38/2018) का अवलोकन करें, जिसमें रावि इयूटी भत्ते की संबंधित डी जसी की गई है।

2. रावि इयूटी भत्ते के बारे में सरकार के नोट्स विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्राप्त आदेशों के अन्तर्गत पर इस मामले की समीक्षा की गई है। राष्ट्रपति सहर्ष विनियमन करते हैं कि 2200 बजे से 0600 बजे की अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए रावि इयूटी भत्ते के प्रति घंटा की दर (मूल वेतन+महागाड़े भत्ता/200) के समान होगी, जो रेल सेवक (बचत के घंटे और विधान की अवधि) नियम, 2005 के साथ चर्चित रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV के अंतर्गत वर्गीकृत अंतर्गत रेल सेवकों की पांच कोटियों के लिए स्वीकार्य होगा। रावि इयूटी भत्ते की पास्ता के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा 43,600/- रु. बतिया गई होगी। इसकी राशि घण्टे कार्यवाही के लिए प्रत्येक ब्य से तैयार की जाएगी। 2200 बजे से 0600 बजे के बीच की गई इयूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट की भरिता (वेतन) का मौजूदा स्वीकरण जारी रहेगा।

3. संबंधित पर्यवेक्षण द्वारा रावि इयूटी आवश्यक होने का प्रमाण-पत्र दिए जाने के अध्याधीन ही रावि इयूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

4. ये निर्देश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशकत्व की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, न्यायना (वेतन एवं भत्ते),
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एंड ए)।-2017/एचडब्ल्यू-1

नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2020

प्रतिनिधि अर्थिक भारत के उप निबंधक एवं महाप्रबंधक पीएलक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली।

जि.ए.
27.09.20
उत्तम सदस्य वित्तपरिचय बोर्ड